प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

18.06.2025 / प्रादेशिक समाचार / 15:00बजे

केन्द्रीय सहायता

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2 हजार 6 करोड़ 40 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ "रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना" को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि एनडीआरएफ के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया। इस धनराशि से राज्य को 2023 मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण होने वाली क्षति व विनाश के कारण रिकवरी व पुनर्निर्माण गतिविधियों में मदद मिलेगी। इसमें 15 सौ 4 करोड़ 80 लाख रुपये राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से केन्द्र का हिस्सा होगा। इससे पूर्व, गृह मंत्रालय ने इस आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को राहत कार्यों के लिय, 12 दिसम्बर 2023 को ही एनडीआरएफ से 6 सौ 33 करोड़ 73 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी दी थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस धनराशि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू ज़िला के निरमंड उपमंडल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागा–सराहन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और उनसे जीवन में मानवीय मूल्यों और आदर्शों को अपनाने का आहवान किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक व सामान्य ज्ञान प्रदान करने पर भी बल दिया।

इस बीच मुख्यमंत्री ने कल शाम बागा–सराहन में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का ध्येय राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास व कल्याण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को छोटे–छोटे कार्यों के लिए जिला मुख्यालय या राज्य सचिवालय आने की जरूरत न पड़े, इसके लिए सरकार स्वयं गांव के द्वार कार्यक्रम द्वारा लोगों के

घर–द्वार समस्याओं का समाधान कर रही है। इससे लोगों के समय और धन की बचत हो रही है।

.....

रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वार्षिक परीक्षा परिणामों में निराशाजनक प्रदर्शन वाले स्कूलों में अध्यापकों की जवाबदेही तय की गई है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल जहां परीक्षा परिणाम शून्य से 25 फीसदी के बीच रहे हैं उन स्कूलों को नोटिस जारी करने के साथ ही अध्यापकों की इंक्रीमेंट भी उस वर्ष के लिए रोक दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में स्कूलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

.....

फास्टटैग–वार्षिक पास

केंद्र सरकार इस वर्ष 15 अगस्त से तीन हजार रुपये की कीमत वाले फास्ट टैग–आधारित वार्षिक पास की शुरूआत करेगी। इससे देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफ़ायती यात्रा संभव होगी। यह वार्षिक पास लागू होने की तिथि से एक वर्ष या अधिकतम दो सौ यात्राओं के लिए वैध होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। यह पास विशेष रूप से गैर–व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए तैयार किया गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि यह कदम राजमार्ग पर आरामदायक यात्रा की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक समर्पित लिंक जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप के साथ–साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा। गडकरी ने कहा कि यह नीति 60 किलोमीटर की सीमा में स्थित टोल प्लाजा के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करेगी और एकल, किफायती लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाएगी।

.....